फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 72 संख्याः 197 प्रभात जयपुर, रविवार 20 फरवरी, 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Was Shut-Down Ever Essential?

Authorities in Germany and other parts of Europe publicly accused WHO of creating public hysteria by declaring normal flu cases as a start of the new pandemic.

Reusing Soft Plastic Bottles

Nicknames From Around The World

प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार के साथ दो घंटे की मुलाकात हुई रात्रि भोज पर

नीतीश व प्रशांत किशोर दोनों को, नजदीक आना सुहा रहा है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनाव-रणनीतिकार प्रशान्त किशोर के बीच शुक्रवार को हुई डिनर-मीटिंग इन रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा तथा मणिपुर के विधानसभा चुनावों में हार की तरफ अग्रसर हो रही है। इसलिये जहाँ इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त अनुमान एवं अटकलें लगाए जा रहे हैं, वहीं राजनैतिक पर्यवक्षेक इसके अलग-अलग अर्थ निकाल रहे हैं।

भाजपा के खराब प्रदर्शन की प्रबल संभावना तथा 10 को घोषित होने वाले पाँच विधानसभा चुनाव-परिणामों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं गोवा में उसकी संभावित पराजय तथा पंजाब में उसके रास्ते में आ रही अड़चनों के कारण इस मीटिंग की महत्ता और भी बढ़ गई है।

अगर भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं गोवा की सत्ता से बेदखल हो जाती है तथा केवल मणिपुर में ही जीत पाती है, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अजेय होने की धारणा टुकड़े-टुकड़े हो जायेगी तथा एक राष्ट्रीय विकल्प के तैयार होने की स्थितियाँ एवं संभावनाएं बहुत प्रबल हो जायेंगी।

- **नीतीश काफी परेशान हैं भाजपा की बिहार इकाई से, जो कि, नीतीश की आलोचना करने व तंग करने का कोई मौका नहीं चूकती।**
- **इसी प्रकार, प्रशांत किशोर भी ममता बनर्जी व उनके महत्वकांक्षी भतीजे की आपसी खींचतान में काफी पिस रहे हैं तथा नया राजनीतिज्ञ ढूंढ रहे हैं, एकजुट व संगठित गैर कांग्रेसी व गैर भाजपायी विपक्ष का नेतृत्व संभालने के लिये।**
- **प्रशांत किशोर के सोच में नीतीश कुमार से ज्यादा कोई उपयुक्त नहीं है, यह भूमिका निभाने के लिये।**
- **नीतीश ने भी अपने दिल्ली निवास पर आयोजित बैठक की खबर जानबूझ कर सार्वजनिक करवायी, जिससे भाजपा भी उन्हें राजनीतिक दृष्टि से हलका व पिटा हुआ मोहरा मानना छोड़े।**

प्रशान्त किशोर, जो 2024 के लोक सभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिये, कुछ दिन से ग़ैर-भाजपा विपक्ष को एक कॉमन मंच पर लाने की कोशिश में हैं, इस समय सभी संभावनाओं और विकल्पों को ही खँगाल रहे हैं जिससे मतदाताओं के सामने मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। टी.एम.सी. को गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ाकर, टी.एम.सी. को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का किशोर का जुआ असफल होता दिखाई दे रहा है तथा इस प्रकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने पर प्रश्न-चिन्ह लग गया है। अब यह कहा जा रहा है कि किशोर इस पद के लिये नीतीश को आगे लाने की कोशिश में हैं जिनके साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल एवं पारस्परिक समझ-बूझ है।

चूँकि, नीतीश कुमार बिहार की भाजपा इकाई के साथ समस्याएँ चलती आ रही हैं, मोदी-शाह की जोड़ी सहित, अन्य केन्द्रीय नेताओं के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के तहत ऐसा कर रही है, इसलिये नीतीश भाजपा का साथ छोड़ने के लिये तैयार हैं। ऐसी स्थिति में किशोर का आत्मविश्वास कुछ और बढ़ जायेगा।

2020 में, जे.डी.यू. में नम्बर दो की हैसियत से काम कर रहे प्रशान्त किशोर को नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया था। उस समय के बाद, इन दोनों के बीच हुई यह पहली मीटिंग एक बंद कक्ष में 2 घंटे तक चली बताते हैं। यह मीटिंग नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभी भी 63 करोड़ लोगों का वैक्सिनेशन नहीं हुआ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़े बताते है कि शनिवार को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का 400वाँ दिन था तथा अब तक भारत की 139 करोड़ जनसंख्या में से केवल 63 करोड़ लोगों के ही टीके लगे हैं। इस प्रकार सरकार का लगवाने का दावा झूठा साबित हो गया है। 31 दिसम्बर 2021 तक सबको टीके लग जायेंगे।

- **स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।**

स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़े बताते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुराने ट्रक व बसों की फिटनेस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में लागू होने जा रहे नये नियमों के तहत, आठ साल से पुराने ट्रकों और बसों के मालिकों को हर वर्ष सरकार अनुमोदित ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनों से अपने वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।

नये ट्रकों तथा बसों के लिये भी, उनकी खरीद के बाद हर दूसरे साल फिटनेस चैक कराना अनिवार्य होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले सड़क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विदेश में पी.एच.डी. आदि की पढ़ाई के लिये स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई सरकार ने

पर, साथ ही यह निर्णय भी लिया कि, किस विषय पर पी.एच.डी. व रिसर्च की जाएगी, उसका अंतिम निर्णय सरकार करेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। सरकार ने अनुसूचित जातियों, खानबदोश आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों के बच्चों और पारम्परिक दस्तकार समुदायों के लिए विदेश में अध्ययन संबंधी छात्रवृत्तियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी है हालांकि गत 6 वर्ष में स्कॉलरशिप के लिए कुछ का ही चयन हुआ है। वर्ष 2021-22 में सबसे कम 39 विद्यार्थियों का ही चयन हुआ था। सरकार ने इसमे कई शर्तें लगा दी है कि विदेशी विश्वविद्यालय में मास्टर्स करने या पी.एच.डी. करने के लिए वे कौनसा विषय चुनेंगे।

नैशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप (एन.ओ.एस.) की संशोधित गाइडलाइन्स गुरुवार को समाज कल्याण एवं सशक्तीकरण मंत्रालय की वैबसाइड पर अपलोड की गई जिसमें साफ कर दिया गया कि अभ्यर्थी भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास या भारतीय सामाजिक विषयों पर अध्ययन

- **सरकार के इस निर्णय से लगा कि, सरकार नहीं चाहती कि, विदेशी युनिवर्सिटीज़ में, भारत की वर्ण व्यवस्था (कास्ट सिस्टम), लिंगभेद, ब्राह्मणवादी सोच व दर्शन आदि पर रिसर्च हो।**

के लिए स्कॉलरशिप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, शोध के शीर्षक की अन्तिम स्वीकृति एनओएस की सलेक्शन-कम-स्क्रीनिंग कमेटी जारी करेगी।

शिक्षाविदों का कहना है कि यह उन विद्यार्थियों पर ज्यादती एवं पाबन्दी लगाना है, जो इससे पहले अपनी पसन्द का शीर्षक लेने के लिये स्वतंत्र थे। यह स्थिति 1950 के दशक से ही चली आ रही थी, जब यह छात्रवृत्ति व्यवस्था शुरू हुई थी। मंत्रालय ने शीर्षक के निर्धारण के मामले में अपने कथन का औचित्य बताते हुये कहा कि यह विद्यार्थियों को की जा रही वित्तीय सहायता है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों के पूरे शिक्षण शुल्क का भुगतान करती है तथा मेडिकल बीमा राशि तथा वीजा शुल्क के अलावा, विद्यार्थी को 15,400 डॉलर का वार्षिक मेंटीनेंस भत्ता तथा 1500 डॉलर का कन्टिन्जेंसी भत्ता देती है।

यद्यपि शर्तों में बताई गई गाइडलाइनें सविस्तार दी गई हैं, लेकिन शिक्षाविदों का कहना है कि इन नियमों से हिन्दू धर्म में जाति-व्यवस्था, भारत में लैंगिक असमानता, ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक परम्पराएं, जाति के संदर्भ में गरीबी तथा ऐसे ही अन्य शीर्षकों पर विदेशी विश्वविद्यालयों में शोध करना प्रतिबन्धित हो जायेगा। उन्होंने कहा कि ये गाइड लाइनें ऐसे समय पर आई हैं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गत चार महीनों में 1.8 लाख इलैक्ट्रिक वाहन बिके

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। 1 सरकार ने अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक 1.8 लाख इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को देखते हुए 40 लाख से अधिक आबादी वाली नौ मेगा सिरीज़ में सरकारी और निजी संस्थानों के इलैक्ट्रिक वीकल चार्जिंग स्टेशन खोलने के कई कदम उठाए हैं। लोगों को

- **सरकार अब ताबड़-तोड़ तरीके से इन इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिये चार्जिंग स्टेशन खोलने में लगी, क्योंकि बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की कमी ही सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है, इलैक्ट्रिक वाहनों के और लोकप्रिय होने में।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एन.आई.ए. ने जोधपुर में दबिश दी

जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में जोधपुर में भी भारी पूछताछ की गयी

जोधपुर, 19 फरवरी (कासं)। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एन आई ए) ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में देशभर में 7 जगहों पर दबिश दी। इसी क्रम में जोधपुर के रतानाड़ा निवासी बरकत अली से भी पूछताछ की गई। ए.आई.ए. टीम ने सुबह बरकत अली के मकान पर दबिश दी और उससे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद टीम वहां से रवाना हो गई। इसके बाद अली को पूछताछ के लिए इन्टैलीजेंस ब्यूरो (आई.बी.) के ऑफिस में बुलाया गया, जहां एन.आई.ए. और आई.बी. की टीमों ने उससे संयुक्त रूप से पूछताछ की। उसे फिर उसके घर ले जाया गया। माना जा रहा है कि एन.आई.ए. अगले कुछ दिन में अली को दिल्ली बुलाकर नए सिरे से पूछताछ कर सकती है।

- **पत्रकार बरकत अली से पांच घंटे पूछताछ की गयी। बरकत अली ने कहा कि, उन्होंने इस आतंकवादी गतिविधि के संबंध में पहले भी सरकार से कुछ इनपुट शेयर किये हैं।**
- **बरकत अली लम्बे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं।**

उल्लेखनीय है कि एन.आई.ए. की टीमों ने जोधपुर के अलावा जम्मू-कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, बड़गांव और गंदेरबल में भी दबिश दी है।

पूछताछ के बाद एन.आई.ए. की टीम निकल गई। इसके बाद बरकत ने मीडिया से भी बातचीत की। उसका दावा था कि वह पत्रकारिता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करता है और कई ऑपरेशन्स में शामिल रहा है। उसने कहा कि "देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, एन.आई.ए. की टीम ने मुझसे जानकारी ली थी। मुझ से कहा गया कि जरूरत पड़ी तो आपसे फिर बात करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई समूह माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी लंबे समय से धमकी दी जा रही है।

2 आई.पी.एस. के साथ 8 लोग पहुंचे:

बरकत ने बताया कि धमकी मिलने के बाद एन.आई.ए. की टीम ने पूछताछ की थी। उसने दावा किया है कि वह इस संबंध में पहले भी सरकार को कुछ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहले दो चरणों में "कमण्डल" पर जोर था, तीसरे चरण में मण्डल पर है

यादव बाहुल्य तीसरे चरण में भाजपा असली समाजवाद की बात कर रही है, सपा के फर्जी समाजवाद के मुकाबले में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कल होने वाले तीसरे चरण के महत्वपूर्ण मतदान से पूर्व दो घटनाक्रम हुए हैं, जो गौरतलब हैं। पहला तो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चुनावी दंगल में एंट्री और दूसरा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गोंडा में किया गया यह दावा कि सपा के "नकली समाजवाद" की तुलना में भाजपा का "समाजवादी" होने का दावा अधिक मजबूत है।

उत्तर प्रदेश चुनाव राज्य के पश्चिमी भाग में सम्पन्न मतदान के दोनों चरणों में प्रभावी रहे "कमण्डल" के चरण से निकलकर अब प्रकट रूप से "मण्डल" चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जो तीसरे दौर में 16 जिलों के 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान के साथ ही शुरु हो जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कई जातियों का जनसांख्यिकीय मिश्रण है। बताया जाता है कि इस चरण की आनुमानित 32 सीटों पर जहां यादव बैल्ट का वर्चस्व है, वहीं कुर्मी, प्रजापति, शाक्य, मौर्य और लोध सहित गैर यादव ओ.बी.सी. मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र की 13 सीटें भी तीसरे चरण में शामिल हैं, जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की करीब 22 प्रतिशत आबादी है। वर्ष 2017 के पिछले चुनावों में भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के तहत

- **अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार ओ.बी.सी. का पिछड़ा व निचला वर्ग अभी भी भाजपा के समर्थन में है, जबकि, ओ.बी.सी. का नया धनाढ्य व महत्वकांक्षी वर्ग, जिसमें कुर्मी व मौर्य शामिल हैं, सपा के साथ है।**
- **पिछले विधानसभा चुनाव में सपा अपने इस गढ़ में ही बुरी तरह पराजित हुई थी, क्योंकि जनता की निगाह में मुलायम सिंह के परिवार में ही काफी झगड़े थे।**
- **इस बार इस छवि को खत्म करने के लिये मुलायम सिंह स्वयं प्रचार में उतरे तथा अखिलेश व शिवपाल को एक ही मंच पर लाकर आमसभा की।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)